



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 16, 1996 (कार्तिक 25, 1918)  
No 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 16, 1996 (KARTIKA 25, 1918)

1 भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, प्रावेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 717	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक प्रावेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के द्वितीय प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राष्ट्रपति, के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होने हैं)	पृष्ठ *
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	975	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और प्रावेश	*
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक प्रावेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	9	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निपेक्षक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबंधित और प्रयोगस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1243
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1611	भाग III—खण्ड 2—ग्रेडेट कार्यालय द्वारा जारी की गई ग्रेडेटों और डिप्लोमों के संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	917
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य व्यक्तियों के प्राधिकार के संबंध में प्रस्ताव द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का द्वितीय भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, प्रावेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	8521
भाग II—खण्ड 2—विशेषक तथा विशेषकों पर प्रचलित समितियों के बिल तथा रिपोर्टें	*	भाग IV—वीर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	305
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के प्रावेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—प्रदेशी और द्वितीय दोनों में अल्प और मुख्य के पंक्तियों को दर्शाने वाला अनुसूचक	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक प्रावेश और अधिसूचनाएं	*		

## CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	717	PART II—SECTION 3—Sub-Sec. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . . .	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	975	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . . .	9	PART III—SECTION —Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .	1243
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .	1611	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . .	917
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . .	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .	5621
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . . .	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . . . . .	305
PART II—SECTION 3—Sub-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi . . . . .	*
PART II—SECTION 3—Sub-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . . . . .	*		

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

## योजना आयोग

नई दिल्ली-110001 दिनांक 24 अक्टूबर 1996

## संकल्प

स. सं. 11011/6/96-97-एआरपीयू—भारत सरकार, योजना आयोग के दिनांक 6 दिसम्बर, 1991 के संकल्प सं 11011/90-कृषि का अधिकरण करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोगों के पुनर्गठित उच्च स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार होगा :—

## अध्यक्ष

1. प्रो. वाई के अलख  
(वैधानिक रूप से)

## सदस्यगण

2. सदस्य (कृषि)  
योजना आयोग
3. सदस्य-सचिव  
योजना आयोग
4. सचिव  
व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय  
नई दिल्ली
5. सचिव  
कृषि और सहकारिता विभाग
6. सचिव  
पशुपालन और डेयरी विभाग
7. सचिव  
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
8. सचिव  
ग्रामीण क्षेत्र और राजगार और गरीबी  
उन्मूलन विभाग
9. सचिव  
बंजर भूमि विकास विभाग
10. सचिव  
जल संसाधन मंत्रालय

## 11. सचिव

पर्यावरण और वन मंत्रालय

12. विशेष सचिव  
योजना आयोग

13—16

विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे चार कृषि उत्पादन आयुक्तों/सचिवों (कृषि) को राज्यों के बीच बारी-बारी से लाया जाना है। निम्नलिखित राज्यों के ए पी सी/सचिव कृषि इस पुनर्गठित समिति के सदस्य होंगे :

- (1) हिमाचल प्रदेश
- (2) तमिलनाडु
- (3) राजस्थान
- (4) मध्य प्रदेश

17—20

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति (जिन्हें एक वर्ष की अवधि में बदला जाना है। शुरू में निम्न लिखित कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति समिति के सदस्य होंगे।

- (1) कुलपति, कोकण कृषि विद्या पीठ, वसोली, महाराष्ट्र।
- (2) कुलपति, विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर नाबिया, पश्चिम बंगाल।
- (3) कुलपति, आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।

(4) कुलपति, राजेन्द्रा कृषि विश्वविद्यालय, पूसा रुमस्ती-पुर, बिहार ।

21. प्रभारी (ए आर पी यू),  
सरदार पटेल आर्थिक एवं सामाजिक अनुसंधान  
संस्थान, थलसेज रोड, अहमदाबाद-380054

संयोजक

22. सलाहकार (कृषि)  
योजना आयोग

2. कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के लिए इस पुनर्गठित  
उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :

(1) केन्द्रीय मंत्रालयों और उच्च राज्य सरकारों के आयोजना विभागों/बोर्डों की पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना के प्रचालनीकरण, सांस्थानीकरण और परिष्करण पर सुझाव देना ।

(2) राज्य योजनाओं और राष्ट्रीय पंचवार्षिक योजनाओं के साथ राज्य योजनाओं और कृषि जलवायु क्षेत्रों के एकीकरण सिद्धान्तों पर सलाह देना और नीति निर्धारित करना ।

(3) विभिन्न जोनल आयोजना टीमें (जंड पी टी एस), राज्य समन्वय समितियाँ और कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना पर कार्य कर रहे अन्य संस्थानों द्वारा कृषि विकास हेतु पायलट कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना अध्ययनों और पूरे किए गए सर्वेक्षणों के परिणामों पर आधारित उपयुक्त नीतियों की सिफारिश करना ।

(4) किसानों को संश्लेषित समझदारी और ए सी आर पी की योजना अवधारणा से अवगत कराने की दृष्टि से उपयुक्त संस्थानात्मक व्यवस्था की सिफारिश करना ताकि दृष्टतम कृषि पैटर्न को विकसित करने में उनके निर्णयों को प्रभावित किया जा सके ।

(5) अध्ययनों और राष्ट्रीय वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में कृषि जलवायु क्षेत्रीय आयोजना से संबंधित किसी भी मामले पर मार्गदर्शन ।

3. उच्च स्तरीय समिति यदि चाहें तो सम्बंधित विषय के विशेषज्ञों को अतिरिक्त सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है ।

4. समिति की बैठकों के संबंध में समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ते/वैनिक भत्ते पर होने वाले व्यय को सरकारी सदस्यों के मामले में सम्बंधित विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों द्वारा और राष्ट्रीय समिति के सहयोजित सदस्यों के मामले में योजना आयोग द्वारा वहन किया जायेगा । योजना आयोग के कृषि प्रभाग द्वारा समिति की प्रबन्ध व्यवस्था की जाएगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रेषित कर दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी हेतु संकल्प को राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए ।

ए. एस. लाम्बा  
निदेशक (प्रशासन)

विस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 1996

संकल्प

विषय : केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का पुनर्गठन

सं. 146/2/94-आई.टी.सी.सी.—करदाताओं और आयकर विभाग के बीच आपसी समझ और सहयोग के विकास एवं संवर्धन के उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए एवं सामान्य स्वरूप की प्रशासनिक तथा प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को दूर करने के उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति के पुनर्गठन से संबंधित दिनांक 29 जनवरी, 1996 के संकल्प सं. 146/2/94-आई.टी.सी.सी. में निम्नीलिखित संशोधन किया जाता है :—

के स्थान पर

गैर-सरकारी सदस्य

क. संसद सदस्य

(1) श्री एन. डीनिस, संसद सदस्य (लोक सभा)

(2) श्री अंकुशराव रविसाहेब टोपे, संसद सदस्य (लोक सभा)

(3) श्री टी. वेंकटराम रेड्डी, संसद सदस्य (राज्य सभा)

(4) श्री चतुरानन मिश्र, संसद सदस्य (राज्य सभा)

पढ़ा जाए

गैर-सरकारी सदस्य

क. संसद सदस्य

(1) श्री एन. डीनिस, संसद सदस्य (लोक सभा)

(2) श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार, संसद सदस्य (लोक सभा)

(4) श्री संजय डालमिया, संसद सदस्य (राज्य सभा)

आदेश

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण के सूचनार्थ इस संबंधित व्यक्तियों के पास भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण के सूचनार्थ इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस. महापात्र  
उप सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

एससी/एसटी (एम) सैल

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्टूबर 1996

संकल्प

विषय : अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मानिटारिंग समिति का गठन

सं. एफ. 8-1/93-एस सी/एसटी (एम)—इस मंत्रालय के दिनांक 28 जुलाई, 1995 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने डा. गिरिजा व्यास, संसद सदस्य (लोक सभा) के स्थान पर श्री एम. ए. फातमी, संसद सदस्य (लोक सभा) को अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मानिटारिंग समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत करने का निर्णय किया है। इस संशोधन के बाद समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :—

अध्यक्ष

- मानव संसाधन विकास मंत्री

सदस्य

- श्री डॉ. टी. मोहम्मद बशीर  
शिक्षा मंत्री, केरल सरकार
- श्री एम. ए. फातमी  
संसद सदस्य (लोक सभा)
- श्री के. एम. खान  
संसद सदस्य (राज्य सभा)
- डा. राजबहादुर गोड  
1-8-1/99, सूर्यनगर  
हैदराबाद-500020
- श्री इमाम-उल-हक  
अध्यक्ष  
राजस्थान उर्वर अकादमी  
ए-3, सुभाष नगर, जयपुर
- डा. ललित अंजुम  
सचिव, अंजुम तरक्की-उर्वर-ए-हिन्द
- श्री अनिल भोंविया  
अध्यक्ष, लोक जुबिश पीरबद  
डी-बलाक, 10 बी, भालना इन्स्टीट्यूशनल अंत्र  
जयपुर
- सदस्य सचिव  
अल्पसंख्यक आयोग
- कुलपति  
जामिया मिलिया इस्लामिया,  
नई दिल्ली
- सचिव (स्कूल शिक्षा)  
बिहार सरकार, पटना

- सचिव (स्कूल शिक्षा)

आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद

- सचिव (स्कूल शिक्षा)

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

- सचिव (स्कूल शिक्षा)

जम्मू और कश्मीर सरकार

जम्मू/श्रीनगर

सदस्य-सचिव

- संयुक्त सचिव

शिक्षा विभाग,

भारत सरकार, नई दिल्ली

- समिति द्वारा किया जाने वाला कार्य है—

“कार्य योजना, 1992 के अध्याय-3-अल्पसंख्यक शिक्षा के कार्यान्वयन की निगरानी करना”।

3. पदेन सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। कार्यकाल दिनांक 28 जुलाई, 1995 के संकल्प के जारी होने की तारीख से शुरू होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संपदक बटजी

संयुक्त सचिव

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्टूबर 1996

सं. के-14011/2/95-यूडी-3 (एम)—शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने शहरी नियोजन तथा डिजाइन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधान मंत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित श्रेणियों में दो द्वि-वार्षिक पुरस्कार होंगे :—

- विशेष कंटेनर के निर्मित परिदृश्यों के परिलक्षित करने वाली कार्यान्वित शहरी नियोजन तथा डिजाइन परियोजनाएं; और
- शहरी नियोजन तथा डिजाइन में, जहां परियोजनाएं प्रक्रियाधीन अथवा कार्यान्वित स्तर पर हों, नूतन विचार/अवधारणाएं और मकशे।

ये पुरस्कार उन सभी भारतीय वास्तुकारों, नगर नियोजकों, तथा सम्बंधित व्यवसायिकों, उनकी फर्मों तथा सरकारी सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टर के संस्थानों/संगठनों के लिए खुले हैं, जिन्होंने भारत के किसी भी क्षेत्र में परियोजनाएं बनाई/चलाई हैं।

पुरस्कार प्रदान करने हेतु पात्र प्रविष्टियों का चयन करने के लिए एक अनुमोदन समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है जिसकी संरचना इस प्रकार होगी :—

#### अध्यक्ष

1. सचिव शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) भारत सरकार।

#### सदस्यगण

2. सचिव, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार।
3. महानिदेशक/अपर महानिदेशक (वास्तुकला)/के. लो. नि. वि.।
4. भारत के मेट्रोपोलिटन शहर के शहरी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष।
5. एक सुविध्यात नगर नियोजक/वास्तुक नियोजक।
6. भारत के स्कूलर आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर का एक प्रतिनिधि।
7. राज्य सरकारों से एक निदेशक (नगर नियोजन)।
8. इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर्स, बम्बई/काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर्स, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि।
9. इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स (इण्डिया), नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि।

10. भारत में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का एक संभारत/संघ निवृत्त निदेशक/इंजीनियरिंग एण्ड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज का उप कुलपति।

11. अपर सचिव/संयुक्त सचिव, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग)।

#### सदस्य सचिव

12. मुख्य नियोजक, नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होगा।

अनुमोदन समिति प्रविष्टियों की जांच व सत्यापन करेगी तथा पुरस्कार पाने वालों के नाम की घोषणा केन्द्रीय शहरी कार्य और रोजगार मंत्री और प्रधान मंत्री का अनुमोदन लेकर की जाएगी। यदि अनुमोदन समिति का यह विश्वास हो कि किसी खास वर्ष में एक या दोनों श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार के लिए कोई पात्र प्रविष्टि नहीं है तो वह उस श्रेणी में द्वितीय (प्रोत्साहन) पुरस्कार के लिए किसी नाम की सिफारिश कर सकता है।

टिप्पणी : श्रेणी 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के सदस्यों को शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी विकास विभाग), भारत सरकार द्वारा अलग से नामित किया जाएगा।

पी. जे. मध्य  
अपर सचिव

#### PLANNING COMMISSION

New Delhi-110001, the 24th October 1996

#### RESOLUTION

No. Q. 11011/6/96-97-ARPU.—In supersession of the Government of India, (Planning Commission) Resolution No. 11011/1/90-Agri. dated 6th December, 1991, it has been decided that the composition of the reconstituted High Level Committee for Agro-climatic Regional Planning shall be as under :

#### Chairman

1. Prof. Y. K. Alagh  
(In personal capacity).

#### Members

2. Member (Agriculture)  
Planning Commission.
3. Member-Secretary  
Planning Commission.
4. Secretary  
Department of Expenditure  
Ministry of Finance  
New Delhi.
5. Secretary  
Deptt. of Agriculture &  
Cooperation
6. Secretary  
Deptt. of Animal Husbandry  
and Dairying.
7. Secretary  
Deptt. of Agricultural  
Research & Education.

8. Secretary  
Department of Rural Areas &  
Employment & Poverty Alleviation,

9. Secretary  
Deptt. of Wasteland Development.

10. Secretary  
Ministry of Water Resources.

11. Secretary  
Ministry of Environment & Forests.

12. Special Secretary  
Planning Commission.

#### 13 to 16

Four Agriculture Production Commissioner/Secretaries (Agri) to be rotated amongst the States representing different regions, APC/Secretary Agriculture of following States shall be members of this reconstituted Committee.

- (i) Himachal Pradesh.
- (ii) Tamil Nadu.
- (iii) Rajasthan.
- (iv) Madhya Pradesh.

#### 17 to 20

Vice Chancellors of State Agricultural Universities (to be rotated after period of one year) Initially Vice Chancellors of following Agricultural Universities shall be members of the Committee.

- (i) Vice Chancellor Konkan Krishi Vidya Peeth, Dapoli, Maharashtra.

(ii) Vice Chancellor, Bidhan Chandro Krishi Vishwavidyalaya, Mohanpur Nadia, West Bengal.

(iii) Vice Chancellor Andhra Pradesh Agricultural University, Rajendranagar, Hyderabad.

(iv) Vice Chancellor, Rajendranagar Agriculture University, PUSA, Samastipur, Bihar.

21. Incharge (ARPU),  
Sardar Patel Institute of Economic & Social Research, Thanej Road, Ahmedabad-380054.

Convenor

22. Adviser (Agri.)  
Planning Commission.

2. The terms of reference of this re-constituted High Level Committee for Agro-climatic Regional Planning are as follows :—

- to give suggestions on operationalisation institutionalisation and refinement of Agro-climatic Regional Planning as part of implementation of five year plans and annual plans to Central Ministries and Planning Departments/Bodies of the State Governments
- to give advice and lay down policy on principles of integration of the State Plans and Agro climatic Regions with the State Plans and National Five Year Plans.
- to recommend appropriate policies based on the findings of the implementation of pilot agro-climatic regional planning projects, studies and surveys completed, for agricultural development by various Zonal Planning Teams (ZPTs), State Coordinating Committees and other institutions working on agro-climatic regional planning.
- to recommend appropriate institutional arrangement for communicating the synthesised wisdom and the planning concept of ACRP to the farmers so as to influence their decision in developing the optimal agricultural patterns.
- to give guidance on any matter related with agro-climatic regional planning as part of formulation and implementation of studies and national annual and five year plans.

3. The High Level Committee may, if it so desire, co-opt experts on the subject as additional Members.

4. The expenditure on TA/DA of the members of the Committee in connection with the meetings of the Committee will be borne in respect of official members by the Departments/ Ministries/State Governments to which the Members belong and by the Planning Commission for co-opted members of the National Committee. The Committee will be serviced by the Agriculture Division, Planning Commission.

#### ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the High Level Committee, all Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. S. LAMBA  
Director (Admn.)

#### MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE) CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi the 31st October 1996

#### RESOLUTION

Subject :—Reconstitution of Central Direct Taxes Advisory Committee.

F. No. 146/2/94-ITCC.—The following amendment is made in the Resolution No. 146/2/94-ITCC dated 29th Jan-

uary, 1996 regarding reconstitution of Central Direct Taxes Advisory Committee to advise the Government on measures for developing and encouraging mutual understanding and Co-operation between tax payers and the Income-tax Department and to advise the Government on measures for removing administrative and procedural difficulties of a general nature :—

For

Non-Official Members

A. Members of Parliament

- Shri N. Dennis, MP (Lok Sabha)
- Shri Ankush Rao Raosaheb Tope, MP (Lok Sabha)
- Shri T. Venkatram Reddy, MP (Rajya Sabha)
- Shri Chaturanan Mishra, MP (Rajya Sabha)

Read

Non-Official Members

A. Members of Parliament

- Shri N. Dennis, MP (Lok Sabha)
- Shri M. P. Veerendra Kumar, MP (Lok Sabha)
- Dr. Ashok Mitra, MP (Rajya Sabha)
- Shri Sanjay Dalmia, MP (Rajya Sabha)

#### ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. MAHAPATRA  
Dy. Secy.

#### MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION) SC/ST (M) CELL

New Delhi, the 11th October 1996

#### RESOLUTION

Subject : Constitution of National Monitoring Committee on Minorities Education.

No. F. 8-I/93-SC/ST (M).—In partial modification of this Ministry's Resolution of even number dated 28th July, 1995, Government of India have decided to nominate Shri M. A. Fatmi, Member of Parliament (Lok Sabha) in place of Dr. Girja Vyas, Member of Parliament (Lok Sabha) as a Member of National Monitoring Committee on Minorities Education. After this modification, the composition of the Committee is as under :

Chairman

- Union Minister of Human Resource Development

Members

- Shri E. T. Mohammed Basheer, Education Minister, Government of Kerala.
- Shri M. A. Fatmi, Member of Parliament (Lok Sabha).
- Shri K. M. Khan, Member of Parliament (Rajya Sabha)
- Dr. Rai Bahadur Gaur, 1-8-1/99, Surva Nagar, Hyderabad-500020

- (vi) Shri Imam-ul-Haque,  
Chairman,  
Rajasthan Urdu Academy,  
A-3, Subhash Nagar, Jaipur.
- (vii) Dr. Khalique Anjum,  
Secretary,  
Anjuman Taraqui-Urdu-E-Hind.
- (viii) Shri Anil Bordia,  
Chairman, Lok Jumbish Parishad,  
D-Block, 10B,  
Jhalana Institutional Area, Jaipur.
- (ix) Member-Secretary,  
Minorities Commission.
- (x) Vice-Chancellor,  
Jamia Millia Islamia,  
New Delhi.
- (xi) Secretary (School Education),  
Government of Bihar,  
Patna.
- (xii) Secretary (School Education),  
Government of Andhra Pradesh,  
Hyderabad.
- (xiii) Secretary (School Education),  
Government of Uttar Pradesh,  
Lucknow.
- (xiv) Secretary (School Education),  
Government of Jammu & Kashmir,  
Jammu Tawi/Srinagar.

#### Member-Secretary

- (xv) Joint Secretary,  
Department of Education,  
Government of India,  
New Delhi.

2. The terms of reference of the Committee is  
"To monitor the implementation of Chapter 3—Minorities' Education of the Programme of Action 1992."

3. The tenure of office of the Members of the Committee other than ex-officio members, shall be three years. The tenure shall take effect from the date of issue of the Resolution dated 28th July, 1995.

#### ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and other members of the Committee.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

CHAMPAK CHATTERJI,  
Jt. Secy.

#### MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT)

New Delhi, the 28th October 1996

No. K-14011/2/95-UDIII (M).—The Ministry of Urban Affairs & Employment have decided to institute the Prime Minister's National Award for Excellence in Urban Planning and Design. There will be two biennial Awards in the following categories :—

- (1) Implemented Urban Planning and Design projects signifying built environment of an exceptional quality; and

- (2) Innovative ideas/concepts and plans in Urban Planning and Design, where the projects are still in the pipeline or at implementation stage.

The awards are open to all Indian Architects, Town Planners, and allied professionals, their firms and Govt., Public and Private Sector Institutions/Organisations who have planned/implemented projects anywhere in India.

In order to select the eligible entries for awarding the Prizes, it has been decided to constitute an Approval Committee with the following composition :—

#### Chairman

- 1. Secretary,  
Ministry of Urban Affairs and Employment,  
(Department of Urban Development),  
Government of India.

#### Members

- 2. Secretary,  
Ministry of Environment and Forests,  
Government of India.
- 3. Director General/Addl. Director General,  
(Arch.), CPWD.
- 4. Vice-Chairman of Urban Development  
Authority in a Metropolitan City in India.
- 5. A renowned Town Planner/Architect Planner.
- 6. One representative of Schools of Planning &  
Architecture in India.
- 7. One Director of Town Planning from the  
State Governments.
- 8. One representative of the Indian Institute of  
Architects, Bombay/Council of Architecture,  
New Delhi.
- 9. One representative of the Institute of Town Planners  
(India), New Delhi.
- 10. One of the serving/retired Directors of IITs/  
Vice-Chancellors of Engineering & Technical  
Universities in India
- 11. Additional Secretary/Joint Secretary,  
Ministry of Urban Affairs & Employment,  
(Department of Urban Development).

#### Member-Secretary

- 12. Chief Planner,  
TCPO.

The tenure of members of the Committee shall be 4 years.

The Approval Committee shall scrutinise and verify the entries and the names of the awardees shall be announced after obtaining the approval of Union Minister for Urban Affairs & Employment and Prime Minister. In the event of the Approval Committee being of the opinion that no entry deserves the first prize under one or both the categories during a particular year, it may recommend the name only for the second (consolation) prize under such categories.

Note : Members for categories 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 would be nominated by Ministry of Urban Affairs and Employment (Department of Urban Development), Government of India separately.

P. J. MATHEW,  
Under Secy.